States at the forthcoming Conference of Chief Ministers of States to maintain the process of implementation of the Plan?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) to (c): State Plans are drawn up in consultation with the State Governments and their further review, especially of the progress of their implementation is also undertaken jointly with them. It is the responsibility of the State Governments to take measures for the proper implementation of their Plans. In the context of this procedure the question of taking any special measures in this respect in the case of States which have non-Congress Ministries, does not arise. There is no proposal to specifically discuss matters relating to the Five Year Plan at the forthcoming Conference of Chief Ministers.

Debts owed by the States to the Centre

679. **Shri C. C. Desai:**
Shri S. S. Kothari:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that some State Governments have recently asked the Central Government to write off debts outstanding against them including the amount of overdrafts on the Reserve Bank of India;

(b) if so, names of the States with details of the amount involved in each case; and

(c) the decision taken by Government in that regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No such request has been received by the Government of India.

(b) and (c) Do not arise.

मानसिक रोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारी

681. **श्री राम भरण :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसिक रोगों से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को केवल एक वर्ष तक मानसिक रोग अस्पतालों में रखा जाता है उसके बाद उनकी, चाहे वे ठीक हो गये हों अथवा न हुए हों, अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). मानसिक रोगो से पीड़ित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मानसिक रोग चिकित्सालयों में अपने इलाज पर 12 महीनों तक के खर्च की ही वापसी मांग सकते हैं । यह समझा जाता है कि जो मानसिक रोगी अस्पताल में 6 महीने इलाज कराने के बाद ठीक नही होता है उसके समाज का उपयोगी सदस्य रहने की सम्भावना नहीं रहती । तथापि यदि संबंधित मानसिक रोग चिकित्सालय का सुपरिन्टेडेन्ट यह प्रमाणपत्र दे दे कि पहले 6 महीनों के उपरान्त और आगे 6 महीने इलाज कराने के बाद रोगी के पूर्णत: ठीक हो जाने की सम्भावना है तो सरकारी खर्च पर इलाज इतने समय तक करवाया जा सकता है । यदि यह अवधि 12 महीने से ऊपर हो जाये तो सरकारी कर्मचारी इलाज के खर्च की वापसी की मांग नही कर सकता ।

Irrigation in Mysore State.

682. **Shri K. Lakkappa:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the Central assistance given to Mysore State since 1964 up-to-date for various irrigation projects, major and medium;